to reopen this mill. Since the NTC has been already overburdened with an onerous responsibility of managing 105 sick cotton textile mills at present, take-over of more sick or closed textile mills for management by the NTC is not favoured. However, any viable proposal from the State Government for the take-over of the sick units will be favourably considered.

झालावाड़ जिले में अफीम का उत्पादन

1714. **श्री चतुर्भुज :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झालावाड़ जिले में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अफीम का कितना उत्पादन हुआ तथा अफीम की खेती का विस्तार कर उसका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) इस कार्य के लिए अफीम उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) पिछले तीन वर्षों में झालावाड़ जिले में उत्पादित अफीम की मात्रा वर्षवार नीचे दिये अनुसार है :—

वर्ष	70 डिग्री घनत्व पर उत्पादित अफीम की मात्रा
	(टनों में)
1974–75.	137
1975–76.	142
1976–77.	98 (अनन्तिम)

झालावाड़ जिले की सभी तहसीलों में पोस्त की खेती की जा रही है । वर्ष 1976–77 में उत्पादन में कमी प्रतिकूल मौसम परिस्थितियोंके कारण हुई । फसल वर्ष 1977–78 के दौरान जिले में पोस्त की खेती बढ़ाने के प्रश्न पर, हमेशा की तरह, लाइसेंसों की जारी करते समय विचार किया जायगा ।

(ख) देश में अफीम का उत्पादन बढ़ाने तथा पोस्त उगाने वाले को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) पोस्त के काश्तकार को अफीम की देय कीमत उसके द्वारा दी गयी अफीम की उपज के आधार पर विसर्पी अनुमाप पर निश्चित की जाती है । जो काश्तकार प्रति हैक्टेयर अफीम की अपेक्षाकृत अधिक उपज देता है उसे अधिक ऊंची दर पर अदायगी की जाती है ।

(ii) प्रत्येक अफीम प्रभाग में पोस्त के उस काश्तकार को नकद पुरस्कार दिया जाता है जो अफीम की सबसे अधिक उपज देता है ।

(iii) कीटनाशक दवाओं तथा उर्वरकों के इस्तेमाल के सम्बन्ध में काश्तकारों को शिक्षा देने के लिये प्रदर्शनों की व्यवस्था की जाती है ।

(iv) अफीम की उपज तथा किस्म में सुधार लाने की दृष्टि से पोस्त के बीजों, मिट्टी तथा उर्वरकों आदि पर प्रयोग करने के लिये पोस्त उगाने वाले कुछ क्षेत्रों में प्रयोगात्मक फार्म बनाये गये हैं । इन प्रयोगों से प्राप्त होने वाले परिणामों को पोस्त काश्तकारों को अफीम की अपनी उपज बढ़ाने के निमित्त उनका मार्ग दर्शन करने के लिये इस्तेमाल किया जायेगा ।

(v) सरकार ने पोस्त की खेती तथा अफीम के उत्पादन के विभिन्न

पहलुओं पर कई दीर्घ-कालीन अनुसन्धान योजनाएं चालू की हैं । इनके परिणाम उपलब्ध होने पर वे अफीम की पैदावार तथा उसकी मार्फीन अन्तर्वस्तु में सुधार लाने में पोस्त के काश्तकारों के लिए सहायक होंगे ।

(vi) काश्तकारों को अपने पोस्त के खतों में उपयोग के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं को उपलब्ध कराने में सहायता की जाती है ।

Relief to Central Government Pensioners

1715. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether the Central Government Pensioners have been given dearness allowance relief at the rate of 5 per cent of their pensions;

(b) if so, since when;

(c) whether any instalment has become due in the event of rise in the cost of living; and

(d) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). The Third Pay Commission had recommended that all future pensioners should be given a relief at the rate of 5 per cent of their pension subject to a minimum of Rs. 5 per month and a maximum of Rs. 25 per month, as and when there was a 16 point rise in the 12 monthly average of the All India Working Class Consumer Price Index (1960=100). In the light of this recommendation, Government had sanctioned 3 instalments of relief to all Central Government pensioners, including those who retired before 1.1.73, with effect from 1.8.73, 1.1.74 and 1.4.74 respectively. Thereafter, keeping in view the resources available, the Central Government pensioners have been given further relief on *ad-hoc* basis to the extent of 10 per cent of pension subject to a minimum of Rs. 10 p.m. and a maximum of Rs. 50 p.m. w.e.f. 1.10.75, to compensate the pensioners for the rise in the cost of living. A special relief at graded rates to the Central Government pensioners has already been announced in the Budget Speech. The orders in the matter will be issued shortly.

Public Distribution System

1716. SHRI M. KALAYANASUNDARAM: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether the present public distribution system covers only some of the major urban centres; and

(b) what is the present need of foodgrains to maintain the existing net work of public distribution system?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) The public distribution system for foodgrains caters not only to the need of urban centres but also rural areas. Out of about 2.44 lakhs Fair Price Shops/Ration Shops functioning in the country, about 1.87 lakhs are functioning in the rural areas.

(b) The Demand for foodgrains, through the public distribution system, depends upon a number of factors, i.e. availability of foodgrains in the open market, their comparative price level, increase in the population etc. It is, therefore, difficult to frame any precise estimate of requirements of foodgrains for the public distribution system. However, during the year 1976, a quantity of about 9.2 million tonnes of